अगस्त-सितंबर में प्रस्तावित है पहला भूमि पूजन समारोह

पहले भूमि पूजन में आकांक्षी जिलों में 81 परियोजनाएं धरातल पर उतरेंगी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। औद्योगिक विकास की मुख्य धारा से दूर रहे प्रदेश के आठ आकांक्षी जिलों में अब उद्योग स्थापित होंगे। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हुए समझौतों के पहले भूमि पूजन में इन जिलों में 36 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की 81 परियोजनाएं धरातल पर उतारने की तैयारी है।

नीति आयोग ने मूलभूत सुविधाओं और संसाधनों के मानकों पर पिछड़े चित्रकूट, फतेहपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली और सोनभद्र जिलों को आकांक्षी घोषित किया है। हालांकि, बीते पांच वर्ष से इन जिलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वैश्विक निवेशक सम्मेलन में इन जिलों के लिए भी बड़ी संख्या में निवेश के लिए करार हुए हैं। अगस्त-सितंबर में पहला भूमि पूजन कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऐसे में औद्योगिक विकास विभाग ने सभी जिलों को निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने का लक्ष्य दिया है। सोनभद्र में 22,323 करोड़ रुपये की 10, चंदौली में 7494 करोड़ की 9, चित्रकूट में 5683 करोड़ की 17, फतेहपुर में 860 करोड़ की 17, बहराइच में 233 करोड़ की 11, श्रावस्ती में 103 करोड़ की दो, बलरामपुर में 150 करोड़ की 7 और सिद्धार्थनगर में 55 करोड़ की 8 परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी है।

चित्रकूट, फतेहपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली और सोनभद्र जिलें हैं आकांक्षी

पश्चिमांचल सबसे आगे

पहले भूमि पूजन में भी निवेश करार को धरातल पर उतारने में पश्चिमी यूपी सबसे आगे रहेगा। गौतमबुद्ध नगर में 229651 करोड़ की 238, 3370 करोड़ की 56, मेरठ में 3211 करोड़ की 30, मुजफ्फरनगर में 2442 करोड़ की 30, बिजनौर में 1897 करोड़ की 53 परियोजनाएं धरातल पर उतरेंगी।

60 परियोजनाएं ही जिलों में भूमि पूजन के लिए तैयार

सरकार ने सभी जिलों को भूमि पूजन के लक्ष्य दिया है। लेकिन अब तक 20 जिलों में सिर्फ 60 परियोजनाएं ही तैयार हैं। इनमें गौतमबुद्ध नगर, बरेली, वाराणसी, हरदोई, उन्नाव, मथुरा, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, औरया की एक-एक परियोजना है। कानपुर नगर, प्रयागराज, गाजियाबाद और कन्नौज में दो-दो, मैनपुरी, हमीरपुर, देवरिया और महराजगंज में तीन-तीन, सहारनपुर में 4, लखनऊ में 6, ललितपुर में 21 परियोजनाएं भूमि पूजन के लिए तैयार है। शेष 55 जिलों में एक भी परियोजना भूमि पूजन के लिए तैयार नहीं हैं।